नए व्यापार समझौतों से भारतीय डेयरी को ख़तरा

भारत के 15 करोड़ छोटे डेयरी किसान, स्थानीय सहकारी समितियां और छोटे विक्रेताओं के मजबूत नेटवर्क ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना दिया है। हमारा देश इस मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पूरे विश्व की डेयरी उद्योग के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है वे अब भारत में भी अपने पैर जमा पाने में कामयाब हो चुके हैं। अभी तक डेयरी उत्पादों के एक मामूली हिस्से को ही भारत में आयात या बाहर निर्यात किया जाता है। परंतु अब कई नई व्यापार समझौता वार्ताएं चल रही हैं जो भारतीय डेयरी का स्वरूप पूरी तरह से बदल देंगी। इन वार्ताओं में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं जो अपने फायदे के लिए छोटे डेयरी उत्पादकों को खत्म कर देना चाहती हैं। इन व्यापार वार्ताओं में प्रमुख हैं – क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) या फिर यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित समझौते जो अभी लंबित हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से ग्रेन (GRAIN) इस बात की छानबीन कर रहा है कि मौजूदा व्यापार वार्ताओं में डेयरी किसान, विक्रेताओं और उपभोक्ता किस प्रकार दांव पर लगे हुए हैं।

> *"एक छोटी डेयरी फॉर्म लगाने में किसान परिवार की पूरी एक पीढ़ी लग जाती है। लेकिन सरकार आर.सी.ई.पी. (RCEP) समझौते में हस्ताक्षर करके एक झटके में इसे नष्ट कर देना चाहती है। इससे भारत का डेयरी क्षेत्र तहस–नहस हो जाएगा।"*
>
> – अजित नवले, डेयरी किसान नेता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने 2017–18 में महाराष्ट्र के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था।[1]

> *"अगर भारत पूरी तरह से आयातक देश बन गया तो हमारे लिए इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं हो सकता"*
>
> – फोंटेर्रा (Fonterra), विश्व का सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक[2]

भारत का डेयरी क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसलिए महत्वपूर्ण भी है। आज भारत के 15 करोड़ डेयरी किसान किसी भी अन्य देश से कहीं ज्यादा दुग्ध उत्पादन करते हैं (सभी प्रजाति के दूध को मिलाकर)। इन डेयरी किसानों में से अधिकतर छोटे भूमि धारक हैं जिनके पास केवल दो–तीन गाय या भैंस हैं। देखा जाए तो भारत का औसत दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। जहां औद्योगिक देशों में औसत उत्पादन 30 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन है वहीं भारत का औसत मात्र 3 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन है। फिर भी देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक और सस्ता खाद्य उत्पादन कर पाने में भारतीय डेयरी किसान कामयाब हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता अब 374 ग्राम प्रतिदिन (2018 में) हो गई है, जो 294 ग्राम प्रतिदिन के वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है।[3] वर्ष 1950 में यह मात्र 130 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति था।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोगों के लिए दूध एक जीवन–शक्ति के समान है। मूल्य के आधार पर यह सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है। इसका मूल्य साल भर में 100 अरब अमेरिकी डॉलर (अंदाजन करीब 7,000 अरब रुपये) के बराबर है। दूध उत्पादन का आधा हिस्सा या तो उत्पादकों द्वारा खुद सेवन किया जाता है या ग्रामीण क्षेत्रों में ही गैर–उत्पादकों को बेच दिया जाता है। बचे हुए दूध को सार्वजनिक सहकारी समितियों या निजी डेयरी को दे दिया जाता है या सीधे घरों में बेच दिया जाता है।

भारत में डेयरी सहकारी समितियां और छोटे विक्रेताओं का एक विशाल और मजबूत नेटवर्क है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं के भुगतान का एक बड़ा हिस्सा सीधे प्राथमिक दुग्ध उत्पादकों तक पहुंच जाता है। किसानों को उपभोक्ताओं के भुगतान का

[1] Direct communication with the Ajit Navle.

[2] Rebecca Howard, "Fonterra eyes India potential", New Zealand Herald, 23 October 2018, https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12147310

[3] Department of Animal Husbandry and Dairying, "An overview of bovine breeding sector in India", http://dahd.nic.in/about-us/divisions/cattle-and-dairy-development

औसतन 70 प्रतिशत से ज्यादा मिल जाता है। सहकारी समितियों में तो 80 प्रतिशत तक प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहां उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री का बड़ा हिस्सा किसान खुद नियंत्रित करते हैं।[4] आज भारत में करीब 170 लाख किसान 186,000 ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। इनमें से 32,000 से भी ज्यादा सहकारी समितियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।[5]

भारत में जिन किसानों के पास भूमि कम है, उनके लिए डेयरी आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। करीब 0.01 हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले एक–चौथाई भारतीय कृषि परिवारों के लिए पशुपालन उनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है।[6]

इसके अलावा, उन लाखों लागों के लिए भी डेयरी आजीविका का एक प्रमुख साधन है जो दूध को किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, या जो दूध से दही, मक्खन या अन्य खाद्य उत्पाद तैयार करते हैं। 'असंगठित क्षेत्र' कहे जाने वाले ये छोटे–मोटे उद्यमी भारत का 80 प्रतिशत दुग्ध वितरण संभालते हैं और बाजार में निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों से दोगुना दूध का वितरण करते हैं।[7]

बॉक्स 1: पूरे दक्षिण एशिया की यही कहानी

पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और नेपाल का डेयरी क्षेत्र कमोबेश भारत की ही तरह है, जो अधिकतर छोटे किसानों और विक्रेताओं के हाथ में है। पाकिस्तान, जो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, में 90 प्रतिशत से भी अधिक दूध का उत्पादन और वितरण, तथाकथित 'असंगठित क्षेत्र' के छोटे विक्रेता ही संभालते हैं। बांग्लादेश में भी डेयरी किसान 10 प्रतिशत से भी कम दूध सहकारी समितियों का बेचते हैं बाकी सारा दूध वे स्थानीय बाजार में या सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। बांग्लादेश के डेयरी क्षेत्र में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है। करीब 70 प्रतिशत किसानों के पास मात्र 1 से 3 गायें हैं और ये देश का 70–80 प्रतिशत दूध का उत्पादन करते हैं। बांग्लादेश के कई भूमिहीन और सीमांत किसानों को पशुपालन से स्थिर नकदी आय मिल जाती है। नेपाल में भी छोटे डेयरी किसानों की संख्या बहुत अधिक है। हालांकि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग, नेपाल के डेयरी क्षेत्र में गाय के दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण भैंस का दूध है। जहां तक छोटे किसानों की बहुतायत का सवाल है, श्रीलंका भी अलग नहीं है। परन्तु अपनी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से अलग, यहां के डेयरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय डेयरी कंपनियां 'नेसले' और 'फोंटेर्रा' की मजबूत उपस्थिति है।

भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में डेयरी सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है (देखें बॉक्स 1: पूरे दक्षिण एशिया की यही कहानी)। यह सैकड़ों लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और चरवाहों, और करोड़ों अन्य लोगों (जो संग्रह, प्रसंस्करण और डेयरी उत्पादों की बिक्री से जुड़े हुए हैं) की आजीविका का एक प्रमुख साधन है। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। अभी तक भारतीय डेयरी क्षेत्र शक्तिशाली वैश्विक महाकाय कंपनियों से बचा हुआ है। इन महाकाय कंपनियों के कारण कई देशों की छोटी–छोटी डेयरियों और प्रसंस्करण उद्यम तबाह हो चुके हैं। भारत अपने प्रशुल्क (import duty) और अन्य व्यापार अवरोधों के कारण अभी तक बचा हुआ है जिसे भारत सरकार ने विकसित देशों के सस्ते डेयरी उत्पादों के आयात को रोकने के लिए लागू कर रखा है ।

परंतु भारत का बाजार इतना बड़ा है कि वैश्विक महाकाय डेयरी कंपनियां ज्यादा दिनों तक इसे अछूता नहीं रहने देंगी। धीरे–धीरे इन्होंने भारतीय डेयरी क्षेत्र में घुसने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। यह सारा काम बहुत चुपके–चुपके पर्दे के पीछे से हो रहा है। ये कंपनियां अपनी–अपनी सरकारों से भारत पर समझौतों की शर्तों को मानने के लिए दबाव डालने के लिए कह रही हैं। अगर भारत इन व्यापार समझौतों में हस्ताक्षर कर देता है तो हमारे घरेलू बाजार के ऊपर कॉरपोरेट नियंत्रण में देर नहीं लगेगी। इस तरह, भारत का डेयरी क्षेत्र एक चौराहे पर खड़ा हुआ है जहां सैकड़ों लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा दांव पर लगी हुई है।

[4] Govind Milk, "FDI in dairy industry in India", 15 January 2018, http://govindmilk.com/fdi-in-dairy-industry-in-india/

[5] Department of Animal Husbandry and Dairying, "An overview of bovine breeding sector in India", http://dahd.nic.in/about-us/divisions/cattle-and-dairy-development

[6] Department of Animal Husbandry and Dairying, "An overview of bovine breeding sector in India", http://dahd.nic.in/about-us/divisions/cattle-and-dairy-development

[7] Vishwanath Kulkarni, "Churning of the milk ocean," Hindu Businessline, 30 July 2018, https://www.thehindubusinessline.com/specials/india-file/churning-of-the-milk-ocean/article24555781.ece

वैश्विक महाकाय डेयरी कंपनियां दरवाजे पर

डेयरी के आयात में शुल्क एवं गैर–शुल्क अवरोधों के कारण भारत में विदेशी डेयरी कंपनियां सीधे व्यापार नहीं कर सकतीं, पर वे स्थानीय डेयरी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम (joint venture), विलय या अधिग्रहण (merger or acquisitions) के जरिए ऐसा कर सकती हैं। यह भी केवल 1991 के बाद से ही संभव हो पाया है, जब नई निजी प्रसंस्करण कंपनियों के ऊपर से प्रतिबंध उठा लिए गए थे।[8] तब से निजी डेयरी कंपनियों का आकार एवं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें से कई निजी कंपनियों को विदेशी कंपनियों और प्राईवेट इक्विटी ग्रूप्स से सहायता मिल रही है। इससे आज निजी कंपनियों का हिस्सा डेयरी बाजार में सहकारी समितियों से ज्यादा बड़ा हो गया है (देखें बॉक्स 2: निजी कंपनियां भारतीय डेयरी बाजार में कदम जमाते हुए)। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के अनुसार जो प्रसंस्करण क्षमता सहकारी–समितियों ने पिछले 30 सालों में अर्जित की थी उतनी क्षमता निजी डेयरी कंपनियों ने पिछले 15 साल में ही हासिल कर ली है।[9]

तालिका 1 : भारत की प्रमुख निजी डेयरी कंपनियां (2019)

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ (Britannia Industries)	'ब्रिटानिया', जो भारत की एक प्रसिद्ध बिस्कुट कंपनी है और जिसका मालिक वाडिया ग्रुप है – ने अभी हाल ही में अपनी डेयरी के विस्तार के लिए एक भारी निवेश कार्यक्रम की शुरूआत की है।
क्रीमलाइन डेयरी (Creamline Dairy)	2015 में 'क्रीमलाइन' का अधिग्रहण भारत की कृषि–व्यापार कंपनी 'गोदरेज एग्रोवेट' ने कर लिया था और तब से उसका तेजी से विस्तार हो रहा है। आज यह भारत की शीर्ष डेयरी कंपनियों में से एक है।
डोडला डेयरी (Dodla Dairy)	डोडला डेयरी दक्षिण भारत में दूध संग्रहण करने वाला सबसे बड़े निजी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी को अमेरीका के टी.पी.जी. (TPG) नामक निजी कंपनी से सहायता प्राप्त है और वर्ष 2019 में इसे विश्व बैंक के आई.एफ.सी. (IFC) से करीब 102 करोड़ रुपये (करीब 150 लाख अमरीकी डॉलर) प्राप्त हुआ है।
ग्रुपे लैक्टेलिस (Groupe Lactalis)	फ्रांसीसी डेयरी कंपनी, लैक्टेलिस ने 2014 में हैदराबाद की 'तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स' को खरीद कर भारत में अपना विस्तार शुरू किया। इसे अमरीका की निजी कंपनी 'कारलाइल ग्रुप' से आर्थिक सहायता मिल रही है। वर्ष 2016 में इसने इंदौर की 'अनिक इंडस्ट्रीज़' का अधिग्रहण किया और 2019 में इसने 'प्रभात डेयरी' को खरीद लिया। इसे राबोबैंक और विश्व बैंक के आई. एफ.सी. (IFC) का आर्थिक समर्थन प्राप्त है जिसने इसे भारतीय डेयरी व्यापार में सबसे शीर्ष पर ला खड़ा किया है।
हटसन एग्रो (Hatsun Agro)	हटसन चेन्नई स्थित एक भारतीय कंपनी है जिसने अपनी शुरूआत आइसक्रीम बनाने से की थी। पिछले दो दशकों में इसने इतनी तेजी से विकास किया कि आज यह देश की सबसे बड़ी निजी डेयरी कंपनियों में से नंबर एक बन गया है जो तरह–तरह के डेयरी उत्पाद बना रही है।
हेरिटेज़ फुड्स (Heritage Foods)	हेरिटेज़ दक्षिण भारतीय डेयरी व्यापार में से सबसे बड़ी निजी कंपनियों में से एक है जो हाल में उत्तर की ओर भी अपना व्यापार बढ़ा रही है। इसने उत्तर में नए कारखाने लगाए हैं और 'वमन मिल्क फुड्स' और 'रिलाइंस रिटेल' के डेयरी व्यापार का अधिग्रहण किया है।

[8] Private sector entrants into dairy processing were effectively blocked through a licensing provision of the Industrial Development and Regulation Act of 1951. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/9835/12/12_chapter%204.pdf

[9] NDDB Annual Report 2010-11, page 8, https://www.nddb.coop/sites/default/files/pdfs/nddb-annual-report percent202010-2011.pdf

आई.टी.सी. लिमिटेड (ITC Limited)	आई.टी.सी. एक ऐसा भारतीय समूह है जो तंबाकू से लेकर आतिथ्य (hospitality) तक का व्यापार करता है। इसने हाल ही में बिहार में एक बड़ी प्रसंस्करण फैक्ट्री लगाकर डेयरी में भी निवेश करना शुरू कर दिया है। इसकी पश्चिम बंगाल में भी एक फैक्ट्री लगाने की योजना है।
क्वालिटी लिमिटेड (Kwality Ltd)	क्वालिटी उत्तर भारत का सबसे बड़े दूध खरीददार में से एक है जिसके पास 6 प्रसंस्करण फैक्ट्रियां हैं। वर्ष 2016 में इसे अमरीकी निजी कंपनी के.के.आर. से करीब 510 करोड़ रुपये (करीब 750 लाख अमरीकी डॉलर) का निवेश प्राप्त हुआ। वर्ष 2018 में के.के.आर. ने क्वालिटी को दिवालिया घोषित कर दिया और तबसे कई विदेशी और राष्ट्रीय कंपनियां इसे लेने की कोशिश कर रही हैं।
नेसले इंडिया (Nestlé India)	स्विटज़रलैंड की महाकाय खाद्य कंपनी, नेसले भारत की सबसे बड़ी दूध की खरीददार है जिसके पास 9 प्रसंस्करण फैक्ट्रियां हैं जो देश भर में फैली हुई हैं।
पराग मिल्क फुड्स (Parag Milk Foods)	पराग, महाराष्ट्र स्थित एक नई कंपनी है जिसे नॉर्वे, अबु धाबी और विश्व बैंक के आई.एफ.सी. (IFC) से आर्थिक मदद प्राप्त है। इसके पास खुद के 2000 गाय डेयरी फार्म हैं जो देश में सबसे बड़ा है। पिछले साल इसने 'दानोन' की प्रसंस्करण फैक्ट्री (हरयाणा स्थित) को खरीद लिया।
पारस (Paras)	पारस भारतीय खाद्य कंपनी, वी.आर.एस. फुड्स की एक डेयरी सहायक कंपनी है।
श्राईबर डाईनामिक्स (Schreiber Dynamix)	श्राईबर डाईनामिक्स, अमेरीकी डेयरी कंपनी श्राईबर फुड (51 प्रतिशत) और भारतीय कंपनी डाईनामिक्स डेयरीज़ का संयुक्त उद्यम है। यह बड़ी खाद्य कंपनियों के लिए ठेके पर डेयरी उत्पाद बनाती है।

तथाकथित संगठित क्षेत्र में जिस प्रकार दूध खरीद में अब सहकारी–समितियों से ज्यादा निजी कंपनियों का योगदान बढ़ता जा रहा है, उससे किसानों के ऊपर काफी बुरा असर पड़ रहा है। भारत की सहकारी–समिति व्यवस्था में राज्य स्तरीय सहकारी महासंघ साल के अंत में दुग्ध उत्पादकों को अपना मुनाफा बांट देते हैं। परंतु नई निजी कंपनियां दुग्ध उत्पादकों के साथ अपना मुनाफा कभी नहीं बांटतीं और न ही वे सहकारी–समितियों की तरह अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करती हैं। दरअसल, ये निजी कंपनियां किसानों से दूध तभी खरीदती हैं जब उनके उत्पाद जैसे स्किम मिल्क पाउडर (skimmed milk powder - मलाई उतारे हुए दूध का पाउडर) और बटर ऑयल (butter oil) के दाम बढ़े हुए हों और उनसे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके।

पिछले 2 वर्षों में जबसे दुग्ध उत्पादों की वैश्विक कीमतों में गिरावट हुई है, इन निजी कंपनियों ने दूध का लेन–देन काफी कम कर दिया है। दूध न बिकने के कारण भारत में प्रचुरता की स्थिति पैदा हो गई है। जब मुनाफा कम हो तो निजी कंपनियां अपना हाथ खींच लेती हैं पर वहीं सहकारी–समितियां किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कभी भी पीछे नहीं हटती हैं, भले ही उसके लिए उन्हें नुकसान भी क्यों न उठाना पड़े।

विदेशी डेयरी कंपनियों के आने से पशुपालन का व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण हो रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय डेयरी एक्शन प्लान के जरिए इसे अपना समर्थन भी दे रही है, जो फोंटेर्रा (Fonterra), लैक्टेलिस (Lactalis), और नेसले (Nestle) जैसी प्रमुख डेयरी कंपनियों को उत्पादन और प्रसंस्करण तकनीकों के आयात को प्रोत्साहित कर रही है। अगर छोटे किसानों के पारंपरिक तरीकों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए तो ये नई तकनीकें बिलकुल भी अनुकूल नहीं है। इनसे केवल बड़ी औद्योगिक खेती को ही लाभ पहुंचता है, जैसे बड़े सघन डेयरी फैक्ट्री फ़ार्म (mega intensive dairy factory farms) जो अब भारत में दिखने लगे हैं।[10] इन बड़े डेयरी फैक्ट्री फ़ार्म में हजारों पशुओं को एंटीबायोटिक (antibiotic) और हार्मोन (hormone) के इंजेक्शन लगा कर जीवन भर बंद जगह पर रखा जाता है। इन सबका पर्यावरण, जलवायु, पशु कल्याण, ग्रामीण अर्थनीति और मजदूरों के साथ–साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर भी भयंकर प्रभाव पड़ता है।

[10] Brighter Green, "Beyond the pail", December 2014, http://brightergreen.org/wp-content/uploads/2014/12/dairypaperbriefwithsourcesfinal.pdf

अभी तक भारत के डेयरी क्षेत्र में निजी कंपनियों का सारा ध्यान 'मूल्य वर्धित उत्पाद' (value added products) जैसे 'चीज़' (एक प्रकार का पनीर), दही या अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के ऊपर ही रहा है। ये कंपनियां इन उत्पादों को खूबसूरत पैकेट में भरकर शहरी उपभोक्ताओं को यह कहकर बेचती हैं कि ये उत्पाद उस दूध से ज्यादा स्वास्थ्यकर विकल्प हैं जिसे छोटे विक्रेता अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल में कनस्तर में भरकर बेचते हैं। कुछ कंपनियां तो धनी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर महंगे प्रोबायोटिक पेय (probiotic drinks), आइसक्रीम तथा अन्य डेयरी उत्पाद तैयार कर रही हैं। कई अन्य छोटी निजी डेयरी डेयरी फ़ार्म एवं कंपनियां स्थानीय नस्ल की गायों जैसे गीर, साहिवाल, थारपरकर, या राठी, इत्यादि के दूध की कीमत बढ़ा देती हैं और यह कहकर बेचती हैं कि उन्हें बिना हाथ से छुए हुए पूरी तरह से यंत्रचलित पद्धिति से तैयार किया गया है, और इसलिए यह ज्यादा पौष्टिक है। परंतु हकीकत यह है कि इन निजी डेयरी कंपनियों के उत्पादों में कुछ भी ज्यादा "स्वच्छ या सुरक्षित" नहीं है (देखें बॉक्स 3: महाकाय डेयरी कंपनियां और खाद्य सुरक्षा)।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब इन बड़ी महाकाय कंपनियों के लिए महज एक शुरुआत भर है। फोंटेर्रा (Fonterra) के शब्दों में यूं कहें कि ये अपनी ''जमीन तैयार'' कर रहे हैं – उस दिन के लिए जब भारत पूरी तरह से अपने बाजार इनके लिए खोल देगा। यह तब होगा जब भारत व्यापार समझौता वार्ताओं में डेयरी बाजार के उदारीकरण के लिए डाले जा रहे दबाव के आगे झुक जाएगा।

बॉक्स 2: निजी कंपनियां भारतीय डेयरी बाजार में पैर जमाते हुए

निजी कंपनियां भारतीय डेयरी क्षेत्र के ऊपर कारपोरेट नियंत्रण स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभा रही हैं (देखें तालिका 2 : भारतीय डेयरी में हाल के निजी सौदे)। शुरुआती समझौतों में से एक 2010 में हुआ जब अमेरिकी कारलाइल ग्रुप ने तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स के 220 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 150 करोड़ रुपये) के हिस्से का अधिग्रहण कर लिया। तिरुमला दक्षिण भारत की एक परिवार के स्वामित्व वाली निजी डेयरी कंपनी थी। अगले 3 सालों (2010 - 2013) में तिरुमला ने करीब 100 चिलिंग स्टेशन (chilling station) को और जोड़ लिया, प्रसंस्करण प्लांट की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई और इसने उत्तर दिशा में वितरण का विस्तार किया। वर्ष 2014 में कारलाइल ग्रुप ने लैक्टेलिस नामक फ्रांसीसी कंपनी को अपना हिस्सा 2500 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 1700 करोड़ रुपये) में यानि 14 गुना ज्यादा दाम में बेच दिया।

तालिका 2 : भारतीय डेयरी में निजी इक्विटी (वित्तीय) कंपनी के सौदे

वर्ष	निवेशक (देश)	भारतीय लक्ष्य (डेयरी कंपनी)	सौदों का मूल्य
2019	दानोन मैनिफेस्टो वेंचर्स (फ्रांस)	ड्रम्स फुड इंटरनैशनल (एपिगामिया दही)	170 करोड़ रुपये
2017	टी.पी.जी (अमेरिका)	डोडला डेयरी	340 करोड़ रुपये
2016	मोतीलाल ओसवाल पी.ई. (भारत)	डेयरी क्लासिक आईक्रीम	107.44 करोड़ रुपये
2016	वरलिनवेस्ट (बेल्जियम), डी.एस.जी कनज़्यूमर (भारत)	ड्रम्स फुड इंटरनैशनल	42.84 करोड़ रुपये
2016	के.के.आर (अमेरिका)	क्वालिटी लिमिटेड	509.3 करोड़ रुपये
2015	टी.वी.एस कैपिटल (भारत)	प्रभात डेयरी लिमिटेड	83 करोड़ रुपये
2015	एइट रोड्स वेंचर्स (अमेरिका)	मिल्क मंत्रा डेयरी प्राईवेट लिमिटेड	85.75 करोड़ रुपये
2014	वेस्टब्रिज कैपिटल (मॉरिशस)	हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	35.22 करोड़ रुपये
2013	कैपवेंट ए.जी. (स्विटजरलैंड)	हांग्यो आइसक्रीम	32.64 करोड़ रुपये
2012	कारगिल वेंचर्स (अमेरिका)	डोडला डेयरी लिमिटेड	107.64 करोड़ रुपये

स्त्रोत : GRAIN based on PricewaterhouseCoopers, Retail and Consumer Quarterly Newsletter Q2 FY 2017
https://www.pwc.in/assets/pdfs/industries/retail-and-consumer/newsletters/retail-and-consumer-quarterly-newsletter-q2-fy-2017.pdf

इस तरह के फायदे की तलाश में तबसे कई वित्तीय कंपनियां इस क्षेत्र में आ गई हैं जैसे – अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी 'टी.पी.जी. ग्रुप' और हॉलैंड की कृषि ऋणदाता कंपनी, 'रोबोबैंक' के साथ–साथ 'दानोन' (Danone) और 'कारगिल' (Cargill) जैसी बहुराष्ट्रीय खाद्य और कृषि–व्यापार कंपनियां। कई मौकों पर इन कंपनियों ने विकास बैंक, जैसे फ्रांस की 'प्रोपारको' या विश्व बैंक की 'अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम' (आई.एफ.सी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निवेश किया है।[1]

पिछले कुछ सालों में, फ्रांस की 'लैक्टेलिस' भारत की सबसे शीर्ष कंपनियों में से एक बन गई है। इसके आगे सिर्फ 'नेसले' है जो भारत में 1960 के दशक से सक्रिय है। वर्ष 2014 में तिरुमला और 2016 में इंदौर स्थित 'अनिक इंडसट्रीज़' के डेयरी विभाग के अधिग्रहण के बाद इस फ्रांसीसी कंपनी ने पहले 'प्रभात डेयरी' और बाद में उसके सहायक, 'सनफ्रेश एग्रो इंडसट्रीज़' का 2019 में अधिग्रहण किया।[2] 'प्रभात डेयरी' का महाराष्ट्र में करीब 75,000 किसानों का नेटवर्क है जहां से करीब 200,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह किया जाता है। प्रभात को खरीदने से लैक्टेलिस को भारत में 2 अतिरिक्त फैक्ट्रियां मिल गईं, जिससे इनकी कुल संख्या 13 हो गई। अब ये प्रतिदिन 23 लाख लीटर दूध की सप्लाई करते हैं। लैक्टेलिस उत्तर भारत में एक और कंपनी के अधिग्रहण के बारे में सोच रही है क्योंकि इसका लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक डेयरी श्रेणी में कम से कम 10 प्रतिशत के बाजार को प्राप्त करना है।

विश्व की सबसे बड़ी डेयरी निर्यातक कंपनी, न्यूजीलैंड की 'फोंटेर्रा' की नजर भी भारत के ऊपर है। वो अधिमान्य व्यापार करार (preferential trade agrement) या फिर सहयोगी उपक्रम (collaborative ventures) की मदद से भारत में प्रवेश करना चाहती है। अगस्त 2018 में फोंटेर्रा ने किशोर बियानी की 'फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर कनज़्यूमर' के साथ एक 50:50 संयुक्त उद्यम की शुरुआत की जिसका नाम रखा 'फोंटेर्रा फ्यूचर डेयरी पार्टनर्स'।[3] इससे फोंटेर्रा भारत में अच्छी तरह से स्थापित हो जाएगा और उसके विस्तार के एजेंडा को पूरा करने में मदद मिलेगी। फोंटेर्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लुकास पैराविसिनी का कहना है – ''जैसा कि हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेजी से विकसित हो रहे बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, इस संयुक्त उद्यम के जरिये हम अपना जमीनी कार्य अच्छे से कर सकेंगे और अपनी विशेषज्ञता का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे।''[4]

फोंटेर्रा का उद्देश्य स्पष्ट है। ते–हां चाउ, जो चीन, दक्षिण और पूर्व एशिया में फोंटेर्रा के प्रमुख हैं, के शब्दों में – ''न्यूजीलैंड के लिए भारत एक विराट अवसर बन जाएगा अगर ये पूरी तरह से आयातक देश के रूप में बदल जाए।'' उन्होंने आगे कहा – ''वर्तमान में भारत मांग और आपूर्ति के मामले में पूरी तरह से संतुलित है। जैसे–जैसे इसका विकास होगा और उत्पादन की रफ्तार कम हो जाएगी तो भारत को अनिवार्य रूप से डेयरी उत्पादों का आयात करना पड़ेगा। बस सवाल यह है कि कब।''[5]

1 The IFC has invested in Parag Milk Foods Pvt. Ltd, Dodla Dairy, Prabhat Dairy (alongside Proparco), and the PRAN Group in Bangladesh.

2 Jitendra, "Lactalis to milk more in India. Why that may worry some", Down to Earth, 18 April 2019, https://www.downtoearth.org.in/news/food/lactalis-to-milk-more-in-india-why-that-may-worry-some-64057

3 "Future Group enters to equal joint venture with Fonterra", Dev Discourse, 8 August 2018, https://www.devdiscourse.com/article/business/105928-future-group-enters-to-equal-joint-venture-with-fonterra

4 "Future Group enters to equal joint venture with Fonterra", Dev Discourse, 8 August 2018, https://www.devdiscourse.com/article/business/105928-future-group-enters-to-equal-joint-venture-with-fonterra

5 Rebecca Howard, "Fonterra eyes India potential", New Zealand Herald, 23 October 2018, https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12147310

बॉक्स 3: महाकाय डेयरी कंपनियां और खाद्य सुरक्षा

सभी पश्चिमी महाकाय डेयरी कंपनियां साफ सुथरी नहीं हैं, न ही ऐसा है कि कोई उनपर उंगली नहीं उठा सकता। चीन को अगस्त 2008 में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा था जब 'फोंटेर्रा' ने 'सान्लु ग्रुप' का 43 प्रतिशत का हिस्सा खरीदा था और दोनों सरकारों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। 'सान्लु ग्रुप' चीन की शीर्ष डेयरी कंपनियों में से एक थी। 'सान्लु–फोंटेर्रा' उत्पादों में मेलामाइन (melamine) की मात्रा काफी अधिक पाई गई। यहां तक की शिशुओं के लिए बनाए गए उत्पादों में भी यह मात्रा अधिक थी। करीब 3 लाख से भी ज्यादा शिशु बीमार हो गए और 6 की किडनी

खराब होने के कारण मौत हो गई। कंपनियों ने तुरन्त सारा दोष किसानों के ऊपर डाल दिया कि उन्होंने ही दूषित दूध बेचा है। दरअसल, "खुद फोंटेर्रा ने सान्लु को गुणवत्ता जांच का सुझाव दिया था पर पूछे जाने पर न्यूजीलैंड की इस कंपनी ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने पार्टनर के उत्पादों की जांच नहीं की है और उन्हें इस हादसे के 1 महीने पहले तक तो यह भी पता नहीं था कि लोग मिलावट भी करते हैं।"[1] फोंटेर्रा का नाम और भी कई खाद्य सुरक्षा संकट के साथ जुड़ा हुआ है।

फ्रांस में लैक्टेलिस कंपनी किसानों को हाशिये पर धकेलने के लिए बदनाम है। न ही तो ये कंपनी खाद्य सुरक्षा समस्याओं का ठीक से निपटान करती है और न ही अपनी संचालन प्रक्रिया की कोई जानकारी साझा करती है। वर्ष 2017 में इनकी एक फ्रांसीसी कंपनी में सालमोनेला (salmonella) का प्रकोप फैल गया जिससे दर्जनों शिशु बीमार हो गए। इस कंपनी ने अपने उत्पाद वापस लेने की प्रक्रिया को ठीक से पूरा नहीं किया जिससे विश्व के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं को संकट से गुजरना पड़ा।[2]

[1] Ben Bouckley, "Fonterra Never checked Sanlu's dairy products prior to deadly China melamine crisis, study warns", Dairy Reporter, 20 June 2014, https://www.dairyreporter.com/Article/2014/06/20/Fonterra-never-checked-Sanlu-s-products-in-China-melamine-scare-Study

[2] "France needs 'food safety police' to avoid new Lactalis crisis: report", Reuters, 18 July 2018, https://www.reuters.com/article/us-france-babymilk-lactalis/france-needs-food-safety-police-to-avoid-new-lactalis-crisis-report-idUSKBN1K824W

व्यापार समझौते भारत की छोटी डेयरियों को तबाह कर देंगे

राष्ट्रीय डेयरी बाजार का स्वरूप काफी समय पहले ही बदल चुका था। दरअसल होता यह है कि कुछ मुट्ठी भर औद्योगिक देश अपने भारी सब्सिडी वाले अधिशेष उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भर देते हैं। इन उत्पादों का विशेष रूप से विकासशील देशों में निर्यात किया जाता है। जाहिर सी बात है कि इसमें वहां की बड़ी डेयरी कंपनियों को ही सारा लाभ पहुंचता होगा, न कि छोटे डेयरी किसानों को जो उन्हें माल सप्लाई करते हैं (देखें बॉक्स 4: फ्रांसीसी डेयरी किसानों के लिए मुश्किल समय)।

बॉक्स 4: फ्रांसीसी डेयरी किसानों के लिए मुश्किल समय

हालांकि यूरोप में डेयरी किसानों को अभी भी सब्सिडी मिलती है पर अति उत्पादन और कम कीमतों के कारण उनका बचे रहना काफी मुश्किल हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, 2017 में फ्रांस में सब्सिडी के साथ दूध का कुल उत्पादन खर्च मात्र 0.56 अमरीकी डॉलर प्रति किलो था, जहां उत्पादकों को केवल 0.39 अमरीकी डॉलर का भुगतान होता था। वो तो यूरोपीय संघ से 0.05 अमरीकी डॉलर प्रति किलो का सीधा अनुदान मिल रहा था जिससे थोड़ी भरपाई हो गई वरना बाकी सब उधार में ही चल रहा था।[1] लगातार बढ़ता कर्ज डेयरी किसान में हताशा पैदा कर रहा है। किसान समुदाय में काफी लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। फ्रांस में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों डेयरी किसान अपनी जान दे रहे हैं। डेयरी किसानों की आत्महत्या की दर फ्रांस की राष्ट्रीय औसत से 50 प्रतिशत ज्यादा है।[2]

[1] "Fewer agricultural subsidies necessitate framework for cost-covering prices", European Milk Board, 9 May 2018, http://www.europeanmilkboard.org/en/special-content/news/news-details/article/fewer-agricultural-subsidies-necessitate-framework-for-cost-covering-prices-1.html?cHash=18ede5bf54d1a42b36209db7ea93c75d

[2] Claire Paccalin, Julie Dungelhoff, "The quiet suicide epidemic plaguing French farmers" 26 October 2018, https://www.france24.com/en/20181026-suicide-epidemic-plaguing-french-farmers-loire-atlantique

भारत जैसे विकासशील देश केवल उच्च प्रशुल्क और गैर–प्रशुल्क अवरोधों (non-tariff barriers) द्वारा ही अपने डेयरी क्षेत्र को इस विकृत वैश्विक बाजार की लूटपाट से बचा सकते हैं। इन उपायों के बिना इन देशों की छोटी डेयरियां तेजी से नष्ट हो जाएंगी। वैश्विक महाकाय डेयरी कंपनियां इन्हें हड़प लेंगी। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भारत को आयात के लिए खोलने का विरोध किया था क्योंकि उस वक्त केंद्र सरकार यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता करने के बारे में सोच रही थी, जिससे भारतीय डेयरी क्षेत्र को यूरोपीय संघ के सब्सिडी युक्त निर्यात के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाने वाला था।[11]

[11] "FTA with EU to hit dairy sector: Modi", The Hindu Business Line, 30 July 2013, https://www.thehindubusinessline.com/economy/fta-with-eu-to-hit-dairy-sector-modi/article23102763.ece

आज भारत का आयात शुल्क 30 से 60 प्रतिशत तक है। इसलिए हमारा डेयरी क्षेत्र अभी तक बचा हुआ है। वर्ष 2003 से भारत ने विभिन्न सैनिटरी (sanitary) और फाइटोसैनिटरी (phytosanitary) आवश्यकताओं को डेयरी आयात के ऊपर लागू कर रखा है, जिसके कारण विशेष रूप से अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में नहीं आ पा रहे हैं।[12] परंतु अब भारत के ऊपर काफी दबाव है कि वह अमेरिकी आयात को इस शर्त पर स्वीकृति दे दे कि उनके उत्पाद वैसे पशुओं के दूध के इस्तेमाल से नहीं बने होंने चाहीए जिनके चारे (feed) में गौ–जाति या अन्य पशुओं के अंश मौजूद हों।[13]

आयात में ये अवरोध तो हैं पर विदेशी डेयरी कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। वे यूरोप और अमेरिका से लेक्टोज़ (Lactose) और व्हे (Whey) जैसी डेयरी उत्पादों का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल खाद्य प्रसंस्करण में होता है। इनके आयात से भारत के सहकारी समिति की डेयरियों और छोटी डेयरियों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी सहकारी–समिति, 'अमूल' के अनुसार, "प्रत्येक माह करीब 1500 टन व्हे पाउडर का देश में आयात किया जा रहा है। इससे हमें अपने माल को सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा है क्योंकि आयातित व्हे की कीमत 40 प्रतिशत आयात शुल्क देने के बाद भी बहुत कम है।"[14]

भारतीय डेयरी स्किम्ड मिल्क पाउडर (skimmed milk powder) के वैश्विक भरमार में भी फंस गई है। इससे कीमतें तेजी से गिर रही हैं। पूरे विश्व में डेयरी किसानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादन राज्य है, दूध की कीमत कम होने के कारण पिछले एक दशक के अंदर वहां की एक–चौथाई डेयरी फॉर्म बंद हो चुकी हैं।[15] भारत में भी स्किम्ड मिल्क पाउडर का भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि दूध का उत्पादन ज्यादा हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हुई हैं।[16] इस राष्ट्रीय अधिशेष (surplus) के कारण दूध की कीमतों पर और किसानों से उसकी खरीद के ऊपर और भी बुरा असर पड़ रहा है। कई देशों ने तो किसानों से गाय का दूध खरीदना ही बंद कर दिया है। 2018 के मध्य में महाराष्ट्र में, जो देश का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, 1 लीटर दूध की कीमत 1 लीटर पानी की बोतल से भी कम हो गई थी। किसानों के पास विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने दूध को सड़क पर बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।[17] इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार को स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात में सब्सिडी देनी पड़ी और डेयरी सहकारी समितियों के दूध और दुग्ध उत्पादों को स्कूलों, शिशु विकास सेवाओं और रेलवे नेटवर्क में मुफ्त में बांटना पड़ा।[18] इस दौरान, दूध की कीमतों में गिरावट के कारण छोटे किसानों के रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर निजी कंपनियां और बड़े किसान फल फूल रहे हैं।

वैश्विक कंपनियों के साथ बहुत सीमित संबंध होने के बावजूद भी भारत की छोटी डेयरियों और किसानों के ऊपर काफी बुरा असर पड़ रहा है। अगर भारत सरकार मौजूदा व्यापार वार्ताओं में डेयरी बाजार खोलने के लिए मान जाती है तो हमारी डेयरियों और किसानों पर उसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि अभी तक भारत ने कोई भी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किसी भी प्रमुख डेयरी उत्पादक राष्ट्र या गुट – जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), अमेरिका या चीन – के साथ नहीं किया है पर इन सबके साथ इस वक्त व्यापार वार्ताएं चल रही हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी) (Regional Comprehensive Economic Partnership) के ऊपर भी बातचीत चल रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2019 तक आर.सी.ई.पी. समझौता वार्ता अपने अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा।

---

[12] "US wants India to lift import ban on dairy products", The Hindu Business Line, 3 April 2012, https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/us-wants-india-to-lift-import-ban-on-dairy-products/article20416523.ece1

[13] Kirtika Suneja, "India ready to allow US dairy imports with riders", Economic Times, 24 December 2018, https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-ready-to-allow-us-dairy-imports-with-riders/articleshow/67236873.cms

[14] Rutam Vora, K.R. Srivats, "Makers of dry and powdered whey get more protection", The Hindu Business Line; New Delhi / Ahmedabad, 1 May 2018; https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/makers-of-dry-and-powdered-whey-get-more-protection/article23731734.ece

[15] Natasha Vaughn, "Why low milk prices are really bad for New York farms", Democrat and Chronicle, 8 March 2018, https://www.democratandchronicle.com/story/news/politics/albany/2018/03/08/why-low-milk-prices-really-bad-new-york-farms/384592002/

[16] "Dairy Quarterly Q2 2018", Rabobank, June 2018

[17] Priyanka Kakodkar, "For Maharashtra dairy farmers, milk is now cheaper than water", Times of India, 24 June 2018 , https://timesiofindia.indiatimes.com/city/kolhapur/for-maharashtra-dairy-farmers-milk-is-now-cheaper-than-water/articleshow/64716085.cms

[18] Rajendra Jadhav, "India's milk powder exports to surge on subsidies, dampen global prices", Reuters, 27 July 2018, https://www.reuters.com/article/us-india-milk-exports-exclusive/exclusive-indias-milk-powder-exports-to-surge-on-subsidies-dampen-global-prices-idUSKBN1KH0GQ ; "Important policy decisions taken and major achievements during the month of June", Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi, 2018: http://dadf.gov.in/sites/default/filess/Monthly percent20Summery percent20for percent20the percent20month percent20of percent20June percent2C percent202018_0.pdf;

डेयरी के क्षेत्र में इन देशों का स्थान

(उत्पादन / व्यापार की मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध)

(जिन देशों के साथ भारत की व्यापार समझौता वार्ता चल रही है वे चिन्हित (रेखांकित) हैं)

विश्व के शीर्ष दूध उत्पादक	भारत, यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, रूस, न्यूजीलैंड
विश्व के शीर्ष दूध निर्यातक	यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, अमेरिका, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया, साऊदी अरब
विश्व के शीर्ष मक्खन निर्यातक	न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ, बेलारूस, अमेरिका, यूक्रेन
विश्व के शीर्ष चीज़ निर्यातक	यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, अमेरिका, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया, साऊदी अरब
विश्व के शीर्ष स्किम्ड मिल्क पाउडर निर्यातक	यूरोपीय संघ, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस
विश्व के शीर्ष मिल्क पाउडर निर्यातक	न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ, उरुग्वे, मेक्सिको, अर्जेंटीना

नोट – निर्यात आंकड़े 2017 श्रेणी वर्ष के अनुसार है जो एफ.ए.ओ. (FAO) के आंकड़ों पर आधारित है।

एफ.टी.ए. नोट – भारत ने अमेरिका के साथ एफ.टी.ए. में रुचि व्यक्त की है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (आर.सी.ई.पी.) और रूस (ई.ए.ई.यू.) के साथ वार्ताएं चल रही हैं। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत दोबारा शुरू होने वाली है। भारत का साऊदी अरब (गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल) और अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे (मरकोसुर) के साथ व्यापार समझौते हैं।

इनमें से अधिकतर मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं में डेयरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन सभी देशों की डेयरी में आक्रमक रुचि है और इनमें से कुछ तो पिछले कई वर्षों से भारत के बाजार में घुसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आयात के मामले में भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि वह केवल उसी डेयरी उत्पाद के आयात को स्वीकृति देगा जो उन पशुओं के दूध से बने हों जिसके चारे (feed) में किसी भी पशु के आंतरिक अंग, रक्त, या टिशु शामिल नही हो। अमेरिका को छोड़कर अधिकांश डेयरी निर्यातक देश इस मांग को लगभग मान चुके हैं। हालांकी भारत के उच्च प्रशुल्क सीमा के ऊपर बातचीत अभी भी अटकी हुई है। इस प्रकार भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए इस उपरोक्त आवश्यकता की शर्त और उसके साथ–साथ डेयरी उत्पादों में 30 से 60 प्रतिशत तक का आयात प्रशुल्क दर की वजह से भारत का बाजार अंतरराष्ट्रीय डेयरी उत्पादों की भरमार से अभी तक बचा हुआ है।

हालांकि एक बार भारत किसी भी एक देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है या अगर आर.सी.ई.पी. से ही जुड़ जाता है तो इन उपायों को बचाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। वर्ष 2000 में शून्य प्रशुल्क का फायदा उठाकर यूरोपीय संघ ने भारी मात्रा में स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल का भारत में निर्यात किया था। हमारे स्थानीय डेयरी उद्योग के ऊपर इसका काफी बुरा असर पड़ने लगा था। तब भारत ने उसका जवाब अपने प्रशुल्क दर को बढ़ाकर दिया था। परंतु यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आर.सी.ई.पी. और भारत के बीच इस वक्त जो भी मुक्त व्यापार समझौता वार्ताएं चल रही हैं उसमें दिये गए शर्तों के आधार पर भारत दुबारा ऐसा नहीं कर पाएगा। भविष्य में किसी भी आयात लहर से अपने किसानों और डेयरी को बचाने के लिए भारत सरकार के पास प्रशुल्क दर को बढ़ाने जैसा कोई भी ठोस उपाय नहीं बचेगा।

पाकिस्तान के अनुभव से भी यही पता चलता है कि एक बार आर.सी.ई.पी. या यूरोपीय संघ – भारत मुक्त व्यापार समझौता के ऊपर हस्ताक्षर हो जाता है तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की डेयरी कंपनियां, जो पहले से ही भारत में मौजूद हैं, भारत के किसानों से दूध खरीदना बंद कर देंगी। वो स्किम्ड मिल्क पाउडर का आयात करेंगी और उनका पुनः प्रसंस्करण (re-process) कर दूध बना लेंगी और भारत में बेचेंगी (देखें बॉक्स 5: महाकाय डेयरी कंपनियों द्वारा पाकिस्तान पर नियंत्रण के लिए मिल्क पाउडर का आयात)। इससे कीमतें गिर जाएंगी और छोटे किसानों और भारतीय डेयरी सहकारी–समितियों और असंगठित डेयरी क्षेत्र के ऊपर काफी बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। कंसोर्सियम फोर ट्रेड एंड डेवेलपमेंट (Consortium for Trade and Development) ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि भारतीय महिला किसानों के ऊपर इनका सबसे गंभीर प्रभाव पड़ेगा।[19]

[19] Roopam Singh, Ranja Sengupta, "The EU India FTA in agriculture and likely impacts on Indian women", CENTAD, December 2009, http://www.centad.org/images/download/Agriculture-Report-Finel-Printing-PDF.pdf

बॉक्स 5: महाकाय डेयरी कंपनियों ने पाकिस्तान पर नियंत्रण के लिए मिल्क पाउडर का किया आयात

पाकिस्तान का 'संगठित' डेयरी क्षेत्र के ऊपर 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों – 'नेसले पाकिस्तान' और 'एन्ग्रो फुड्स' – का मजबूत नियंत्रण है। नेसले पाकिस्तान, स्टिजरलैंड की एक महाकाय कंपनी की शाखा है और एन्ग्रो फुड्स एक डच (Netherlands) महाकाय कंपनी, 'फ्रीलैंड–कैम्पिना की सहायक कंपनी है। उन्होंने पाकिस्तान में दूध संग्रह और वितरण के बाजार को आपस में बांट लिया है और छोटे किसानों को व्यवसाय से बाहर निकाल दिया है। अपने फायदे के लिए दूध के दामों को नियंत्रित करने के लिए कभी–कभी ये कंपनियां स्थानीय डेयरी किसानों से दूध लेना बिलकुल बंद कर देती हैं। उसके बदले वे पाउडर और तरल दूध का आयात करते हैं। जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूध के पाउडर के दाम गिर जाते हैं तो ये कंपनियां भारी मात्रा में दूध आयात कर लेती हैं, जो उन्हें स्थानीय बाजार से दूध लेने की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है।

स्रोत: Saad Sarfaraz Sheikh, "Cash cows", Herald, 1 February 2017, https://herald.dawn.com./news/1153231

कुछ लीक हुए समझौते के दस्तावजों से पता चलता है कि भारत–यूरोपीय संघ, भारत–ई.एफ.टी.ए. (EFTA), या आर.सी.ई.पी. व्यापार समझौतों में ऐसे कई अध्याय शामिल हैं जिनसे भारतीय डेयरी क्षेत्र के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। इनमें से प्रमुख हैं – मानकों का सामंजस्य (harmonisation of standards), निवेशक साझेदार देशों के साथ राष्ट्रीय बर्ताव, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी विनियम (sanitary and phytosanitary regulations), व्यापार, निवेश उदारीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार के ऊपर तकनीकी अवरोधों पर नियम, इत्यादि।[20]

- *डेयरी नियम एवं विनियम का सामंजस्य :* इससे वे लाखों छोटे एवं सीमांत डेयरी किसान प्रभावित होंगे जो सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं या निजी डेयरियों को दूध की सप्लाई करते हैं। भारत में डेयरी क्षेत्र का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा असंगठित है। इसलिए निजी क्षेत्र अपने विकास के लिए बाजार के इस हिस्से को हथिया लेना चाहता है। संगठित क्षेत्र को हराने के लिए बड़ी वैश्विक डेयरी कंपनियां भारत में अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रही हैं। पूरी संभावना है कि ये विदेशी कंपनियां अपने देशों की ही तरह भारत में भी मानकों के सामंजस्य की मांग करें। इसके लिए वे इन द्विपक्षीय या आर.सी.ई.पी. या मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं में अपने देशों की सरकार के जरिए भारत पर दबाव बनाएंगे। ये मानक किसी से भी जुड़े हो सकते हैं जैसे – पशु और खेत संचालन, पशु स्वास्थ्य एवं कल्याण, बहीखाता, स्वच्छता इत्यादि।
- *निवेशक देशों के साथ राष्ट्रीय बर्ताव (National Treatment) :* इस प्रावधान के अनुसार भारत में विदेशी डेयरी कंपनियों के अधिकार और सुविधाएं घरेलू कंपनियों के समान होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार अपने छोटे डेयरी किसानों की मदद के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा सकेगी या इन विदेशी कंपनियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत को विदेशी डेयरी कंपनियों और घरेलू कंपनियों के साथ एक समान व्यवहार करना होगा।
- *भौगोलिक संकेत (Geographical Indications):* इसका इस्तेमाल विदेशी डेयरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा और वह भी भारतीय उत्पादकों की कीमत पर। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत यूरोपीय संघ अपने 130 डेयरी उत्पादों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है।[21] एमेंटाल, फिटा, गौडा, ग्रुएरे, मोत्ज़ेरेला और पारमेसन – ये सारे 'चीज़' (एक प्रकार का पनीर) के ब्रांड नाम हैं जो मूलतः यूरोपीय संघ से हैं और जिनके नाम सुरक्षित हैं। अमूल जैसी भारतीय डेयरी निकाय जो इस प्रकार के 'चीज़' बनाती हैं, अब भारत–यूरोपीय संघ एफ.टी.ए. के तहत उनका उत्पादन नहीं कर पाएंगी। समझौता वाताओं पर यह भी निर्भर करता है कि क्या भारतीय डेयरी अपनी चीज़ (Cheese) को यूरोपीय चीज़ जैसे 'मोत्ज़ेरेला' या 'मोत्ज़ेरेला–जैसा' भी बता पाएंगे या नहीं।
- *सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानक (Sanitary and Phytosanitary Standards):* व्यापार वार्ताओं में यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारतीय डेयरी निर्यात को रोकेगा। यूरोपीय–संघ के उच्च सैनिटरी मानक भारतीय डेयरी उत्पादकों को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करेंगे क्योंकि भारत की डेयरी सहकारी समितियों में बाजार

[20] See https://www.bilaterals.org/?+-leaks-

[21] Kavaljit Singh, "India-EU FTA: Where is the Europe's Trade Agenda Headed", Special Report, 23 February 2012, https://www.madhyam.org.in/wp-content/uploads/2014/07/India-EU-FTA-Where-is-the-Europe_s-Trade-Agenda-Headed.pdf

निगरानी व्यवस्था (market surviellance systems) और 'स्रोत पता लगाने की व्यवस्था' (traceability) काफी कमजोर है। वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) के पास सैनिटरी मानकों से होने वाले 36 विभिन्न अवरोधों की एक सूची है जो भारत से यूरोपीय–संघ को होने वाले निर्यात को रोकेंगे। इस वक्त, यूरोपीय संघ भारत से आयात को इसलिए अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि ऐसी धारणा है कि भारत में पशु *पैर और मुंह* (foot and mouth disease) की बीमारियों से संक्रमित रहते हैं और उनका रख रखाव यूरोपीय संघ के मानकों के अनुसार नहीं होता है। पूरी संभावना है कि यूरोपीय संघ–भारत एफ.टी.ए, भारत–ई.एफ.टी.ए. एफ.टी.ए, और आर.सी.ई.पी. की मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं में इन सैनिटरी नियमों को और भी कठिन बना दिया जाएगा जिससे छोटे उत्पादकों को व्यापार से बाहर किया जा सके और सारा मुनाफा बड़ी कंपनियों को दिलाया जा सके।

- *निवेश उदारीकरण और निवेशक सुरक्षा (Investment Liberalization and Investor Protections):* आज के मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं में यह एक केंद्रीय मुद्दा है कि सभी निवेशक देशों के लिए एक समान स्तर सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रमुख उपाय हैं – "उचित और न्यायसंगत व्यवहार" (fair and equitable treatment), बेदखली के मामले में मुआवजा (compensation in case of expropriation), विदेशी निवेशकों के लिए "राष्ट्रीय" और "सबसे पसंदीदा राष्ट्र" (most favoured nation) व्यवहार, स्थानीय प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं से मुक्ति, पूंजी का मुक्त स्थानांतरण, एवं निवेशक–राष्ट्र विवाद निपटान (investor-state dispute settlement - ISDS) प्रावधान, जो बड़ी महाकाय कंपनियों को सरकारों से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, इत्यादि। निवेश उदारीकरण से, आमतौर पर, सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय डेयरी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान हो जाएगा। और जहां तक बात निवेशक–राष्ट्र विवाद निपटान (ISDS) की है वहां यह देखना होगा कि भारत इन वार्ताओं में किस हद तक बहस कर पाता है। अगर भारत ठीक से बहस नहीं कर पाया तो भारत को अपने उन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कानूनों को बदलना होगा जो इन कंपनियों के मुनाफे को कम करेंगी वरना वे भारत सरकार पर मुकदमा कर देंगी।
- *निर्यात प्रतिबंध हटाना (Removal of Export Measures):* भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत यह यूरोपीय संघ की एक प्रमुख मांग है।[22] घरेलू खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए समय–समय पर भारत चावल, गेहूं, चीनी इत्यादि खाद्य उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता है। यदि भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है तो भारत अपनी जनसंख्या की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कभी भी डेयरी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा।

आर.सी.ई.पी. का जो प्रभाव भारतीय डेयरी उद्योग के ऊपर पड़ने वाला है वह एक गहन चिंता का विषय है क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की भारतीय डेयरी क्षेत्र में आक्रमक रुचि है। भारत के 15 करोड़ डेयरी किसानों की तुलना में न्यूजीलैंड में सिर्फ 12,000 डेयरी किसान हैं और ऑस्ट्रेलिया में इनकी संख्या मात्र 6300 है। किसानों की संख्या इतनी कम होने पर भी न्यूजीलैंड 220 लाख मैट्रिक टन के वार्षिक दुग्ध उत्पादन में से 190 लाख मैट्रिक टन का निर्यात करता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने 150 लाख मैट्रिक टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन में से कुल 40 लाख मैट्रिक टन का निर्यात करता है। इसलिए न्यूजीलैंड की 'फोंटेर्रा' और ऑस्ट्रेलिया की 'बेगा' डेयरी कंपनियां इस उम्मीद में हैं कि आर.सी.ई.पी. की मदद से उन्हें भारत के विशाल डेयरी बाजार में प्रवेश मिल जाएगा जहां वे अपना अतिरिक्त उत्पाद बेच सकेंगे।

भारत की डेयरी सहकारी समितियों को ये डर है कि अगर दूध और दुग्ध उत्पादों के ऊपर से आयात शुल्क को आर.सी.ई.पी के तहत हटा दिया गया तो इससे न सिर्फ डेयरी कंपनियों और सहकारी समितियों पर बुरा असर पड़ेगा बल्कि 15 करोड़ डेयरी किसानों की आजीविका पर भी खतरा मंडराने लगेगा। 'अमूल' के प्रबंध निदेशक, आर.एस. सोधी के अनुसार, "आज पूरे एशिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर है। न्यूजीलैंड को हमारे बाजार में मुफ्त प्रवेश देने से न सिर्फ हमारे किसानों को चोट पहुंचेगी बल्कि हमारे उपभोक्ताओं को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार–चढ़ाव झेलने पड़ेंगे।"

"भारत की हालत भी चीन जैसी हो सकती है" – आर.एस. सोधी ने आगे कहा। "वर्ष 2008 में न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के बाद चीनी डेयरी क्षेत्र का तेजी से पतन हुआ। व्यापार समझौते के बाद चीनी डेयरी क्षेत्र का विकास दर 25 प्रतिशत से गिरकर मात्र 2 प्रतिशत हो गया।"[23]

---

[22] Afsar Jafri, Ranja Sengupta, "Trade and Investment Treaties: Implications for Agriculture & Food Security in India", September 2015, http://isid.org.in/pdf/WTOpaper01.pdf

[23] Vishwanath Kulkarni, "Dairy sector opposes free market access to New Zealand products", 31 July 2014, https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/Dairy-sector-opposes-free-market-access-to-New-Zealand-products/article20832738.ece

निष्कर्ष

भारतीय डेयरी और करोड़ों छोटे डेयरी किसान और उनके स्वदेशी नस्ल के पशुओं का भविष्य छिन जाने के कगार पर है। छोटे डेयरी उत्पादकों के ऊपर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है। सहकारी समितियों का भी यही हाल है। वैश्विक निवेशक और उनके द्वारा नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय बाजार के मानकों से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। अगर आर.सी.ई.पी, भारत–यूरोपीय संघ, भारत–ई.एफ.टी.ए तथा अन्य मुक्त व्यापार समझौतों को रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब अधिकतर छोटे किसान डेयरी क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

भारत का डेयरी क्षेत्र 15 करोड़ लोगों की आजीविका, पोषण और खेती की निरंतरता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन्हें महाकाय बहुराष्ट्रीय डेयरी कंपनियों से बचाकर रखा जाए। व्यापार समझौताओं से सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही फायदा पहुंचेगा जो देसी कंपनियों और किसानों के व्यापार को खत्म कर देंगी।

आगे पढ़ें:

- GRAIN and the Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) report 2018 "Big meat and dairy companies are heating up the planet", https://www.grain.org/en/article/5999-big-meat-and-dairy-companies-are-heating-up-the-planet
- GRAIN 2017 report "Grabbing the bull by the horns: it's time to cut industrial meat and dairy to save the climate", https://www.grain.org/en/article/5643-grabbing-the-bull-by-the-horns-it-s-time-to-cut-industrial-meat-and-dairy-to-save-the-climate
- GRAIN's 2017 "Highlights from the Peoples' Summit against FTAs and RCEP", https://www.grain.org/en/article/5763-highlights-from-the-peoples-summit-against-ftas-and-rcep
- GRAIN, IATP and Heinrich Böll Foundation 2017 "Big meat and dairy's supersized climate footprint", https://www.grain.org/en/article/5825-big-meat-and-dairy-s-supersized-climate-footprint
- GRAIN 2017 report, "How RCEP affects food and farmers", https://www.grain.org/en/article/5741-how-rcep-affects-food-and-farmers
- GRAIN and Ashlesha Khadse, "RCEP in India: A creamy deal for transnational dairy corporations, growing resistance from farmers", https://www.grain.org/en/article/5815-rcep-in-india-a-creamy-deal-for-transnational-dairy-corporations-growing-resistance-from-farmers
- GRAIN 2014 report, "Defending people's milk in India", https://www.grain.org/en/article/4873-defending-people-s-milk-in-india
- GRAIN 2011 report "The great milk robbery: How corporations are stealing livelihoods and a vital source of nutrition from the poor", https://www.grain.org/e/4259

ग्रेन (GRAIN) एक छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय गैर–लाभकारी संगठन है जो समुदाय नियंत्रित और जैव–विविधता आधारित खाद्य व्यवस्था के लिए संघर्षरत छोटे किसानों और सामाजिक आंदोलनों के हित में कार्य करता है। ग्रेन हर साल अनेकों रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट विभिन्न मद्दों के ऊपर एक ठोस शोध दस्तावेज होते हैं जिनमें गहराई से पृष्ठभूमि की जानकारी और उनका विश्लेषण होता है। *''नए व्यापार समझौतों से भारतीय डेयरी को ख़तरा''* ग्रेन के अंग्रेजी के लेख *Indian dairy under threat from new trade deals* का हिन्दी अनुवाद है।

ग्रेन (GRAIN) की रिपोर्ट का सम्पूर्ण संग्रह को http://www.grain.org से प्राप्त किया जा सकता है।

पता :

GRAIN

Girona 25 pral., 08010 Barcelona, Spain

Tel: +34 93 301 1381, Fax: +34 93 301 16 27, Email: grain@grain.org